JOURNAL OF THE ROYAL LAUREATES ACADEMY

www.rlaindia.org

विदिशा जिले के नगरीय निकायों द्वारा क्रियान्वित शासकीय योजनाओ के प्रभाव का अध्ययन

पुष्पेन्द्र कुमार अहिरवार
शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म. प्र.)
डॉ. एस. पी. जैन
प्राध्यापक (वाणिज्य अध्ययनशाला एवं शोध केंद्र), महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म. प्र.)

सारांश

शासन द्वारा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा उन्हें आवश्यक संसाधनों एवं सुविधाओं से सशक्त बनाना होता है। विदिशा जिले के नगरीय निकायों द्वारा संचालित विभिन्न शासकीय योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं उज्ज्वला योजना आदि स्थानीय निवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। इन योजनाओं का प्रभाव हितग्राहियों के जीवन स्तर पर व्यापक रूप से देखा जाता है, जो कि उनके आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार, वित्तीय समावेशन एवं अन्य सुविधाओं में परिलक्षित होता है। विदिशा जिले के नगरीय निकायों द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं ने शहरी विकास को गति दी है और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह अध्ययन इन योजनाओं की उपयोगिता तथा भविष्य में सुधार की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है।

मुख्यशब्द- विदिशा जिला, नगरीय निकाय, शासकीय योजनाएँ, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, शहरी विकास

प्रस्तावना

शासकीय योजनाएँ किसी भी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाएँ चलाई जाती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, उन्हें सशक्त बनाना और उनके लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना होता है। ये योजनाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्य सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण, कृषि सुधार, तकनीकी विकास, डिजिटल इंडिया, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लागू की जाती हैं। इनका प्रभाव न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर पड़ता है, बल्कि पूरे समाज के समग्र विकास में भी योगदान देता है।

भारत में शासकीय योजनाओं का इतिहास स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही शुरू हुआ, जब सरकार ने गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और सामाजिक विकास पर ध्यान देना प्रारंभ किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करती है और लोगों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। इस योजना के माध्यम से गरीब तबकों को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, जिससे वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस योजना का प्रभाव ग्रामीण मजदूरों के जीवन स्तर पर देखा गया है, क्योंकि इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है, जिससे उनके परिवारों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना से हजारों लाभार्थियों को अपने खुद के घर का सपना पूरा करने का अवसर मिला है। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी है और वे एक स्थायी आश्रय प्राप्त कर सके हैं। इसी प्रकार, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) ने लोगों की स्वच्छता संबंधी आदतों में बदलाव लाया है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और पर्यावरण भी स्वच्छ बना है। खुले में शौच मुक्त (ODF) भारत की दिशा में यह योजना बहुत प्रभावी साबित हुई है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ने से जलजनित बीमारियों में कमी आई है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी व्यय में भी बचत हुई है।

शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) जैसी योजनाएँ लागू की हैं, जिनका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। इन योजनाओं के तहत गरीब तबकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें, पोषण आहार और अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) भी एक महत्वपूर्ण पहल है, जो युवाओं को विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित करती है, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर

मिलते हैं। इन योजनाओं ने बेरोजगारी की समस्या को कम करने में योगदान दिया है और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - PMJAY) एक क्रांतिकारी कदम है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से गरीबों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ मिल रही हैं और उन्हें आर्थिक तंगी के कारण इलाज में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मातृत्व सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) और जननी सुरक्षा योजना (JSY) चलाई गई हैं, जो गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करती हैं। इन योजनाओं का सीधा प्रभाव मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) में कमी के रूप में देखा गया है।

कृषि क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) जैसी योजनाएँ किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक रही हैं। PM-KISAN के तहत किसानों को हर वर्ष सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे कृषि संबंधी खर्चों को पूरा कर सकें। PMFBY के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि से सुरक्षा मिलती है, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की गई हैं, जिससे किसानों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और वे आधुनिक तकनीकों को अपनाने में सक्षम हुए हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ महत्वपूर्ण रही हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जिससे वे धुएं रहित रसोई का लाभ उठा सकती हैं। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और उनका समय भी बचा है, जिसे वे अन्य उत्पादक कार्यों में लगा सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है।

डिजिटल इंडिया योजना के तहत देश में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया गया है, जिससे ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन लेन-देन और इंटरनेट सेवाओं की पहुँच ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बढ़ी है। इससे लोगों को सरकारी सेवाएँ आसानी से मिल रही हैं और भ्रष्टाचार में कमी आई है। जन धन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया है, जिससे गरीबों के बैंक खाते खुले हैं और वे बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

हालाँकि, कई सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी देखी गई हैं, जैसे कि जागरूकता की

कमी, लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुँच न होना, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जटिलताएँ और राजनीतिक हस्तक्षेप। कई बार लाभार्थियों को योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं होती, जिससे वे उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इसके अलावा, नौकरशाही तंत्र में भ्रष्टाचार और लालफीताशाही के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी होती है, जिससे उनके प्रभाव को सीमित किया जा सकता है।

इसलिए, यह आवश्यक है कि सरकार न केवल नई योजनाएँ शुरू करे, बल्कि पहले से चल रही योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। जागरूकता अभियानों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जानी चाहिए, जिससे वे उनका लाभ उठा सकें। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए और भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, योजनाओं की जमीनी हकीकत की समीक्षा कर समय-समय पर उनमें सुधार किया जाना चाहिए, ताकि वे अधिक प्रभावी बन सकें।

अध्ययन के उद्देश्य

1. नगरीय निकायों द्वारा योजनाओ का हितग्राहियो के संतुष्टि का विश्लेषण।

परिकल्पना

परिकल्पना 1

HO: सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से हितग्राहियों के जीवन स्तर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है।

H1: सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से लाभार्थियों के जीवन स्तर पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

परिकल्पना 2

HO: सरकारी योजनाएँ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुँचती हैं, और उनके द्वारा लाभ का उपयोग नहीं किया जाता है।

H1: सरकारी योजनाएँ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचती हैं, और उनके द्वारा लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है।

शोध प्रविधि

इस अध्ययन का उद्देश्य विदिशा जिले के नगरीय निकायों द्वारा क्रियान्वित शासकीय योजनाओ के प्रभाव का अध्ययन का मूल्यांकन करना है। अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन से नागरिकों को वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं और उनके जीवन स्तर में किस हद तक सुधार हुआ है। शोध के लिए विदिशा जिले के नगर पालिका परिषद और नगर परिषद क्षेत्र से पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया गया हैं। न्यादर्श के रूप में चुना गया और पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधि नमूने का चयन किया गया। आँकड़ों का संकलन व्यक्तिगत रूप से किया गया; शोधकर्ता ने क्षेत्र भ्रमण कर उत्तरदाताओं को अध्ययन के उद्देश्य से अवगत कराया और प्रश्नावली प्रदान की। डेटा का विश्लेषण व्यवस्थित रूप से किया गया और तालिकाओं, ग्राफ़ तथा प्रतिशत मानों के माध्यम से परिणाम प्रस्तुत किए गए। सांख्यिकीय उपकरणों में एनोवा (ANOVA), समवर्ग राशि (SS), डिग्री ऑफ़ फ्रीडम (df), मीन स्क्वायर (MS) और F-क्रिटिकल मान शामिल थे। इस प्रकार यह शोध प्रविधि योजनाओं के प्रभाव का व्यवस्थित मूल्यांकन सुनिश्चित करती है।

न्यादर्शन प्रक्रिया

अध्ययन का उद्देश्य विदिशा जिले के नगरीय निकायों द्वारा क्रियान्वित शासकीय योजनाओ का हितग्राहियों के जीवन स्तर पर प्रभाव के बीच संबंध को जानना है। प्रतिदर्श में विदिशा जिले के नगर पालिका परिषद विदिशा, नगर पालिका परिषद गंजबासोदा, नगर पालिका परिषद सिरोंज, नगर परिषद कुरवाई, नगर परिषद लटेरी, नगर परिषद शमशाबाद क्षेत्र के पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया गया था। जिसमे नगर पालिका परिषद विदिशा से 200 लोगो को चुना गया था, जिसमे से 100 पुरुष, और 100 महिलाएँ थी, इसी प्रकार नगर पालिका परिषद गंजबासोदा से 200 लोगो को चुना गया था, जिसमे से 100 पुरुष, और 100 महिलाएँ थी, इसके बाद नगर पालिका परिषद सिरोंज से से 200 लोगो को चुना गया था, जिसमे से 100 पुरुष, और 100 महिलाएँ थी, इसी प्रकार नगर परिषद कुरवाई 70 लोगो को चुना गया था, जिसमे से 35 पुरुष, और 35 महिलाएँ थी, इसके बाद नगर परिषद लटेरी से 70 लोगो को चुना गया था, जिसमे से 35 पुरुष, और 35 महिलाएँ थी, और अंत में नगर परिषद शमशाबाद से 80 लोगो को चुना गया था, जिसमे से 40 पुरुष, और 40 महिलाएँ थी। अत: कुल मिलाकर विदिशा जिले के नगर पालिका परिषद और नगर परिषद क्षेत्र से 410 पुरुष और 410 महिलाएँ शामिल थी। इनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष से अधिक तक की थी।

सांख्यिकीय प्रयोग

शोध अध्ययन में निम्न लिखित सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया गया है-

प्रतिशत मान, एनोवा, समवर्ग राशि (SS), डिग्री ऑफ फ्रीडम (df), मीन स्क्वायर (MS), एफ -क्रिटिकल मान

विश्लेषण और व्याख्या

आंकड़ों का विश्लेषण और ब्याख्या एक अध्ययन या शोध के निकाय से विशिष्ट तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय प्रक्रिया को लागू करना है।

जनसांख्यिकीय जानकारी

तालिका-1 उत्तरदाता का लिंग

लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत दर
पुरुष	410	50%
महिला	410	50%
कुल	**820**	**100**

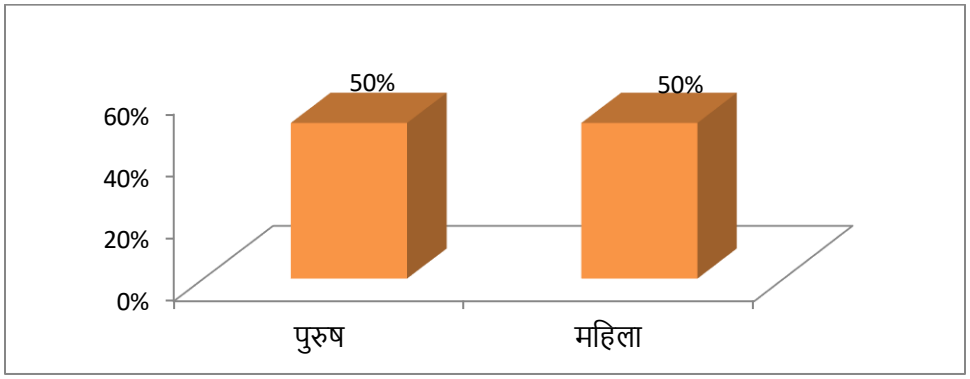

चित्र-1 उत्तरदाता का लिंग

तालिका-1 में उत्तरदाताओं के लिंग के आधार पर उनकी संख्या और प्रतिशत दर्शाया गया है। इस तालिका के अनुसार कुल 820 उत्तरदाता शामिल किए गए, जिनमें पुरुषों की संख्या 410 है, जो कि कुल उत्तरदाताओं का 50 प्रतिशत है। इसी प्रकार, महिलाओं की संख्या भी 410 है, जो कि कुल उत्तरदाताओं का 50 प्रतिशत है।

आयु (Age):

तालिका-2 उत्तरदाता की आयु

आयु	आवृत्ति	प्रतिशत दर
18-25 वर्ष	90	10.98%
26-35 वर्ष	130	15.85%
36-45 वर्ष	220	26.83%
46-60 वर्ष	310	37.80%
60 वर्ष से अधिक	70	8.54%
कुल	**820**	**100**

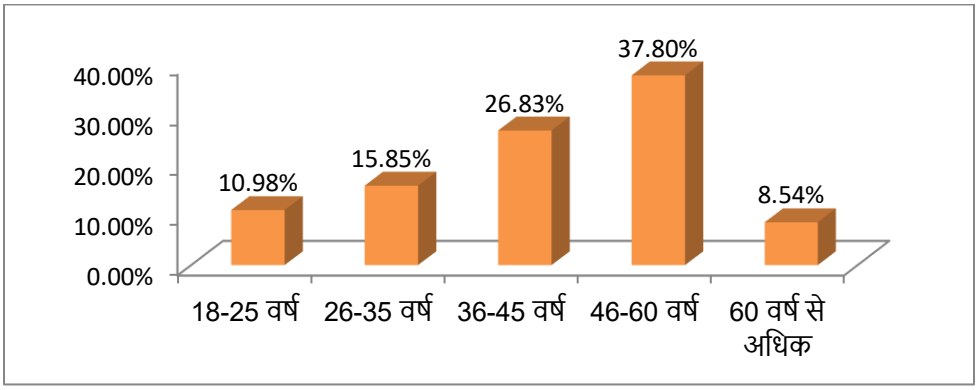

चित्र-2 उत्तरदाता की आयु

तालिका-2 में उत्तरदाताओं का वर्गीकरण उनकी आयु के आधार पर किया गया है। इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन में विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को शामिल किया गया है, जिससे शोध को व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। अध्ययन में कुल उत्तरदाताओं की संख्या 820 है। इनमें से सबसे अधिक उत्तरदाता 46 से 60 वर्ष की आयु श्रेणी में आते हैं, जिनकी संख्या 310 है, जो कि कुल उत्तरदाताओं का 37.80 प्रतिशत है। यह इंगित करता है कि इस शोध में अधेड़ आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी सर्वाधिक रही है, जो अपने अनुभव और सामाजिक दृष्टिकोण के कारण शोध को परिपक्व दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इसके बाद 36 से 45 वर्ष आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 220 (26.83%) है। यह वर्ग भी समाज का एक सक्रिय और कार्यशील वर्ग है, जो नीति, व्यवहार और सामाजिक बदलावों को गहराई से समझने में सक्षम होता है। 26 से 35 वर्ष आयु वर्ग के उत्तरदाता 130 (15.85%) हैं, जो अपेक्षाकृत युवा और प्रौढ़ अवस्था के बीच का वर्ग है, तथा सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में सक्रिय भागीदारी करता है। 18 से 25 वर्ष आयु

वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या 90 (10.98%) है। यह वर्ग नवयुवकों का है, जिनकी सोच नवीन और ऊर्जा से भरपूर होती है। सबसे कम सहभागिता 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की रही है, जिनकी संख्या 70 (8.54%) है। यद्यपि संख्या में कम, परंतु इस वर्ग का अनुभव और परिपक्व दृष्टिकोण शोध को संतुलन प्रदान करता है।

स्थान

तालिका-3 उत्तरदाताओ के स्थान का नाम

स्थान का नाम	आवृत्ति	प्रतिशत दर
विदिशा	200	24.39%
गंजबासोदा	200	24.39%
सिरोंज	200	24.39%
कुरवाई	70	8.54%
लटेरी	70	8.54%
शमशाबाद	80	9.75%
कुल	**820**	**100**

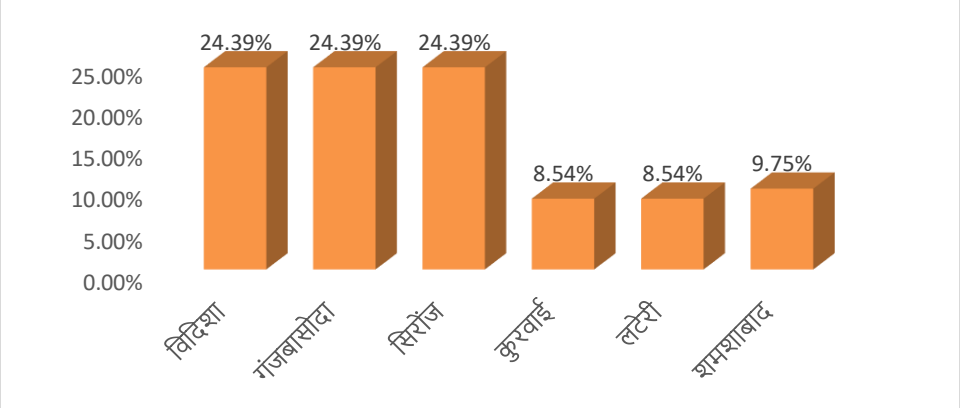

चित्र -3 उत्तरदाताओ के स्थान का नाम

दिए गए आंकड़ों की तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इसमें विदिशा, गंजबासोदा और सिरोंज से सर्वाधिक 200-200 उत्तरदाता शामिल किए गए हैं, जो कुल नमूने का 24.39%–24.39% भाग बनाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इन तीनों स्थानों को अध्ययन में प्रमुखता से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त कुरवाई और लटेरी से 70-70 उत्तरदाता लिए गए हैं, जो कुल का 8.54%–8.54% भाग हैं। वहीं शमशाबाद से 80 उत्तरदाता सम्मिलित किए गए हैं, जिनका प्रतिशत 9.75% है। इस प्रकार यह तालिका दर्शाती है कि बड़े शहरी या अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि छोटे कस्बों या तहसीलों से अपेक्षाकृत कम संख्या में उत्तरदाताओं को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर यह वितरण अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न स्थानों की विविधता को संतुलित रूप से प्रदर्शित करता है।

उद्देश्य 1. नगरीय निकायों द्वारा योजनाओ का हितग्राहियो के संतुष्टि का विश्लेषण।

आपको योजना से लाभ मिलने में कितनी संतुष्टि मिली

तालिका-4 योजना से लाभ मिलने में संतुष्टि

संतुष्टि स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत दर
बहुत संतुष्ट	390	47.56%
संतुष्ट	240	29.27%
असंतुष्ट	120	14.63%
बहुत असंतुष्ट	70	8.54%
कुल	**820**	**100**

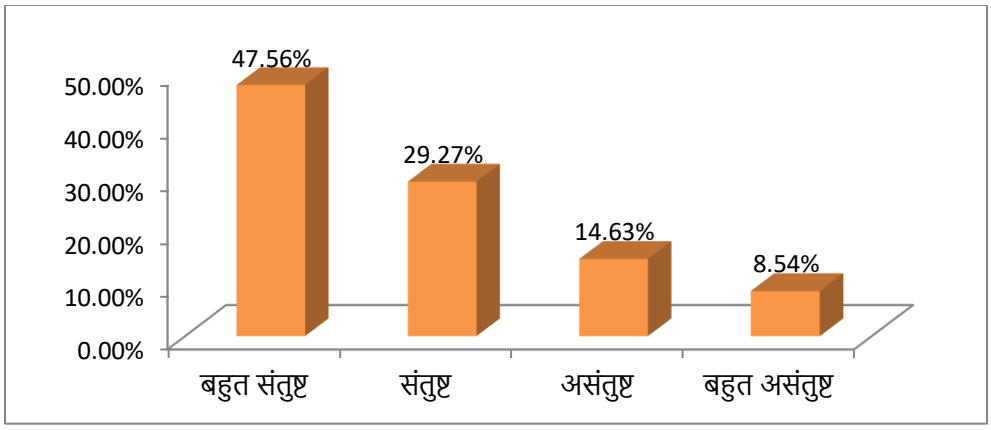

चित्र-4 योजना से लाभ मिलने में संतुष्टि

तालिका-4 में यह दर्शाया गया है कि उत्तरदाताओं की संतुष्टि का स्तर शासकीय योजनाओं से प्राप्त लाभ के संदर्भ में क्या है। यह तालिका यह स्पष्ट करती है कि लोग शासकीय योजनाओं से मिलने वाले लाभ को किस हद तक सकारात्मक रूप से अनुभव कर रहे हैं और योजनाओं से उनकी संतुष्टि का स्तर कितना है। इस तालिका के अनुसार, 390 उत्तरदाता (47.56%) ने कहा कि वे बहुत संतुष्ट हैं। यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि लगभग आधे से अधिक उत्तरदाता शासकीय योजनाओं से प्राप्त लाभ से पूरी तरह संतुष्ट हैं। इसका मतलब यह है कि ये योजनाएँ उन लोगों की ज़रूरतों को सही तरीके से पूरा कर रही हैं और लोग इन योजनाओं के परिणामों से काफी प्रभावित हैं। यह भी दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन प्रणाली अपेक्षाकृत प्रभावी है, जिससे लाभार्थियों को अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इसके बाद, 240 उत्तरदाता (29.27%) ने कहा कि वे संतुष्ट हैं। यह संख्या दर्शाती है कि एक और बड़ी संख्या में लोग योजनाओं से मिले लाभ से खुश हैं, हालांकि उनकी संतुष्टि शायद उतनी उच्च नहीं है जितनी उन लोगों की है जो "बहुत संतुष्ट" हैं। इस समूह में लोग योजनाओं से कुछ हद तक संतुष्ट हैं, लेकिन वे कुछ सुधारों या अतिरिक्त लाभों की उम्मीद भी कर सकते हैं। 120 उत्तरदाता (14.63%) ने कहा कि वे असंतुष्ट हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि एक महत्वपूर्ण संख्या में लोग योजनाओं से उतनी संतुष्ट नहीं हैं, जितनी संतुष्टि की उम्मीद की जाती है। यह दर्शाता है कि कुछ लोग योजनाओं के परिणामों से असंतुष्ट हैं और उनके लिए इन योजनाओं का प्रभाव अपेक्षित नहीं रहा। अंत में, 70 उत्तरदाता (8.54%) ने कहा कि वे बहुत असंतुष्ट हैं। यह संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी यह संकेत देती है कि कुछ लोग पूरी तरह से असंतुष्ट हैं और इन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने में उन्हें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखाई देता। यह स्थिति उन क्षेत्रों को उजागर करती है जहाँ योजनाओं को सही तरीके से लागू करने या सही लाभार्थियों तक पहुँचने में सुधार की आवश्यकता हो सकती है।

योजना की जानकारी मिलने से लाभ प्राप्त करने तक की प्रक्रिया कितनी सुविधाजनक थी

तालिका-5 योजना की जानकारी मिलने से लाभ प्राप्त करने तक की प्रक्रिया

प्रक्रिया स्तर	आवृत्ति	प्रतिशत दर
बहुत सरल	380	46.34%
सामान्य	250	30.49%
कठिन	110	13.41%
बहुत कठिन	80	9.76%
कुल	**820**	**100**

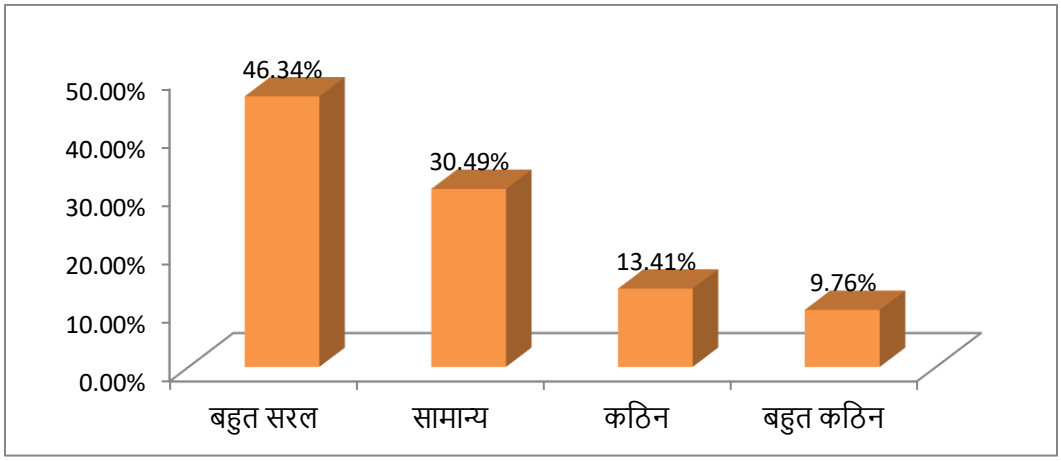

चित्र-5 योजना की जानकारी मिलने से लाभ प्राप्त करने तक की प्रक्रिया

तालिका-5 में यह दर्शाया गया है कि शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने से लेकर लाभ प्राप्त करने तक की प्रक्रिया उत्तरदाताओं के लिए कितनी सरल या कठिन रही। यह तालिका यह समझने में मदद करती है कि लोग शासकीय योजनाओं से जुड़ी प्रक्रिया को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और इसे लागू करने में कितनी कठिनाई महसूस करते हैं। इस तालिका के अनुसार, 380 उत्तरदाता (46.34%) ने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत सरल है। इसका मतलब यह है कि लगभग आधे से अधिक लोग योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं महसूस करते हैं और इसे सुगमता से पूरा कर पाते हैं। यह दर्शाता है कि योजनाओं का प्रचार, कार्यान्वयन और लाभार्थियों तक पहुँचने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सहज और सरल है।

250 उत्तरदाता (30.49%) ने कहा कि प्रक्रिया सामान्य है। यह संख्या दर्शाती है कि एक और महत्वपूर्ण संख्या में लोग योजनाओं से लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को जटिल नहीं मानते, लेकिन वे इसे पूरी तरह से सरल नहीं मानते। इस समूह के लोग कुछ मामूली बाधाओं या औपचारिकताओं का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें किसी बड़ी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। इसके विपरीत, 110 उत्तरदाता (13.41%) ने कहा कि प्रक्रिया कठिन है। इसका मतलब यह है कि कुछ लोग योजना के लाभ प्राप्त करने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो प्रक्रिया को उनके लिए कठिन बनाते हैं। यह संकेत देता है कि कुछ प्रक्रियाएँ अत्यधिक जटिल हो सकती हैं, जो योजना का पूरा लाभ उठाने में बाधा डाल सकती हैं। 80 उत्तरदाता (9.76%) ने कहा कि प्रक्रिया बहुत कठिन है। यह संख्या छोटी होने के बावजूद यह बताती है कि कुछ लोग योजनाओं से लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं जो लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया को असहनीय या अत्यधिक कठिन बना देती हैं।

परिकल्पना का परीक्षण

परिकल्पना:-1

HO: सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से हितग्राहियों के जीवन स्तर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है।

H1: सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से लाभार्थियों के जीवन स्तर पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

तालिका 6: परिकल्पना:-1 के लिए एनोवा परिणाम – सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से हितग्राहियों के जीवन स्तर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है।

विविधता का स्रोत	एसएस	डीएफ	एमएस	एफ	एफ क्रिट	परिणाम
समूहों के बीच	12.45	1	12.45	5.32	3.84	H_0 अस्वीकार
समूहों के अंतर्गत	189.72	808	0.23			
कुल	202.17	809				

तालिका 6 शीर्षक "परिकल्पना-1 के लिए एनोवा परिणाम – सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से हितग्राहियों के जीवन स्तर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है" के अंतर्गत ANOVA (Analysis of Variance) तकनीक

का उपयोग करके यह जांचा गया है कि क्या सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से हितग्राहियों के जीवन स्तर पर कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं। इस तालिका में 'समूहों के बीच' विविधता (SS=12.45, DF=1, MS=12.45) और 'समूहों के अंतर्गत' विविधता (SS=189.72, DF=808, MS=0.23) को दर्शाया गया है। प्राप्त F मान 5.32 है, जबकि F-क्रिटिकल (F crit) मान 3.84 है। चूँकि प्राप्त F मान, F-क्रिटिकल मान से अधिक है (5.32 > 3.84), अतः शून्य परिकल्पना (H_0), जिसे कहा गया था कि "सरकारी योजनाओं का हितग्राहियों के जीवन स्तर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है", को अस्वीकार कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि आँकड़ों के अनुसार सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का हितग्राहियों के जीवन स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अर्थात् योजनाओं ने जीवन स्तर में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाया है, जिसे केवल संयोग या गलती नहीं माना जा सकता।

परिकल्पना:-2

HO: सरकारी योजनाएँ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुँचती हैं, और उनके द्वारा लाभ का उपयोग नहीं किया जाता है।

H1: सरकारी योजनाएँ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचती हैं, और उनके द्वारा लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है।

तालिका 7: परिकल्पना:-2 के लिए एनोवा परिणाम – सरकारी योजनाएँ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुँचती हैं, और उनके द्वारा लाभ का उपयोग नहीं किया जाता है।

विविधता का स्रोत	एसएस	डीएफ	एमएस	एफ	एफ क्रिट	परिणाम
समूहों के बीच	8.26	1	8.26	4.78	3.84	H_0 अस्वीकार
समूहों के अंतर्गत	139.25	808	0.17			
कुल	147.51	809				

तालिका 7 में परिकल्पना-2 के परीक्षण हेतु एक-मार्गीय एनोवा (ANOVA) का उपयोग किया गया है, जिसमें यह जांचा गया है कि क्या सरकारी योजनाएँ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुँचती हैं और वे उनका उपयोग नहीं करते हैं। इस संदर्भ में शून्य परिकल्पना (H_0) यह मानी गई कि "सरकारी योजनाएँ लाभार्थियों तक नहीं पहुँचतीं और उनके द्वारा लाभ का उपयोग नहीं किया जाता।" तालिका के अनुसार, समूहों के बीच (Between

Groups) की समवर्ग राशि (SS) 8.26, डिग्री ऑफ फ्रीडम (df) 1, और मीन स्क्वायर (MS) 8.26 है। वहीं समूहों के अंतर्गत (Within Groups) SS 139.25, df 808 और MS 0.17 है। कुल समवर्ग राशि 147.51 है और कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम 809 है। एनोवा परीक्षण से प्राप्त F-मूल्य 4.78 है, जबकि F-क्रिटिकल मान 3.84 है। चूँकि प्राप्त F मान, F-क्रिटिकल से अधिक है (4.78 > 3.84), यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस आधार पर शून्य परिकल्पना (H_0) को अस्वीकार कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी योजनाएँ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचती हैं और वे उनका उपयोग करते हैं। शून्य परिकल्पना का खंडन यह संकेत करता है कि योजनाओं की पहुँच लाभार्थियों तक सुनिश्चित हुई है और उनका क्रियाशील उपयोग भी देखा गया है। यह निष्कर्ष नीतिगत स्तर पर एक सकारात्मक संकेतक है, जो यह दर्शाता है कि योजनाओं का उद्देश्य अपने लक्षित समूह तक पहुँचने में सफल रहा है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विदिशा जिले के नगरीय निकायों द्वारा क्रियान्वित शासकीय योजनाओ के प्रभाव का अध्ययन का मूल्यांकन करना था, जो पांच प्रमुख उद्देश्यों और पांच परिकल्पनाओं पर आधारित था। पहले उद्देश्य के तहत, हितग्राहियों को पहुँचने वाली योजनाओं के लाभ का विश्लेषण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ विभिन्न वर्गों तक पहुँच रहा है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में वितरण में सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। इसके साथ-साथ परिकल्पना-1 के अंतर्गत प्रस्तुत एनोवा (ANOVA) विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का हितग्राहियों के जीवन स्तर पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। परीक्षण में समूहों के बीच प्राप्त F-मूल्य 5.32 है, जो कि निर्धारित F-क्रिटिकल मान 3.84 से अधिक है। इस अंतर के कारण शून्य परिकल्पना (H_0) – "सरकारी योजनाओं का हितग्राहियों के जीवन स्तर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है" – को अस्वीकार कर दिया गया है। यह परिणाम इस ओर संकेत करता है कि सरकारी योजनाएँ, जिनका क्रियान्वयन अध्ययन क्षेत्र में किया गया, हितग्राहियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में प्रभावी रही हैं। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन योजनाओं ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।

इसके साथ-साथ परिकल्पना-2 के अंतर्गत एक-मार्गीय एनोवा विश्लेषण द्वारा यह मूल्यांकन किया गया कि क्या सरकारी योजनाएँ वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुँचतीं और उनके द्वारा लाभ का उपयोग नहीं किया जाता है। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, समूहों के बीच का F-मूल्य 4.78 है, जो F-क्रिटिकल मान 3.84 से अधिक

है। यह अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, जिससे शून्य परिकल्पना (H_0) को अस्वीकार कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि सरकारी योजनाएँ अपने लक्षित लाभार्थियों तक न केवल पहुँची हैं, बल्कि वे उनका उपयोग भी कर रहे हैं। यह निष्कर्ष इस ओर संकेत करता है कि योजनाओं का क्रियान्वयन अपेक्षाकृत प्रभावी रहा है और लाभार्थी समुदाय द्वारा उनकी स्वीकृति तथा उपयोग सुनिश्चित हुआ है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि योजनाओं की पहुँच और प्रसार नीति-निर्माताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अन्बुथम्बी, बी., एवं चंद्रशेखरन, एन. (2017). ग्रामीण युवाओं पर स्किल इंडिया का प्रभाव: एक दृष्टिकोण। आईसीटीएसीटी जर्नल ऑन मैनेजमेंट स्टडीज, 3(1), 457-460।
2. श्रीधर, एस. एन. (2024). प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना पर एक हीयूरिस्टिक अध्ययन: सूक्ष्म ऋण योजना के संदर्भ में। एशियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इकॉनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, 42(6), 339–349. https://doi.org/10.9734/ajaees/2024/v42i62497
3. हारन, पी., एवं क्लोनर, एस. (2020). बेहतर बाल स्वास्थ्य के लिए मातृत्व नकद सहायता? भारत की आईजीएमएसवाई/पीएमएमवीवाई मातृत्व लाभ योजना का प्रभाव। यूनिवर्सिटी ऑफ हीडलबर्ग, अर्थशास्त्र विभाग, चर्चा पत्र श्रृंखला संख्या 689।
4. कुमार, एस., जैन, पी., एवं गर्ग, यू. (2024). प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मातृ, शिशु स्वास्थ्य और पोषण पर प्रभाव, चुनौतियाँ एवं अवसर: साहित्य समीक्षा। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, 30, 2419-24। doi: 10.53555/kuey.v30i3.6077
5. बेहरा, एस. (2023). प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई): एक समीक्षा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ होम साइंस, 9, 11–15।https://www.homesciencejournal.com/archives/2023/vol9issue3/PartA/9-2-60-910.pdf
6. बंसल, के. (2025). भारत में अप्रयुक्त विशेष-उद्देश्य निधियों पर विचार: भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (बीओसीडब्ल्यू) कल्याण निधि का मामला। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, 6(5), 13–21। doi: 10.47505/IJRSS.2025.5.2

7. लहरिया, सी. (2009). संस्थागत प्रसव हेतु नकद प्रोत्साहन: प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात देखभाल से जोड़ना भारत में 'निरंतर देखभाल' सुनिश्चित कर सकता है। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, 34, 15–18। doi: 10.4103/0970-0218.45370
8. शर्मा, एम. पी., सोनी, एस. सी., भट्टाचार्य, एम., दत्ता, यू., गुप्ता, एस., एवं नंदन, डी. (2009). जयपुर जिले, राजस्थान में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल स्तरों पर जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव का मूल्यांकन। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, 53, 177–182।
9. अनीता। (2017). प्रधानमंत्री मोदी की पीएमजेजेबीवाई एवं पीएमएसबीवाई बीमा योजनाओं पर एक वर्णनात्मक अध्ययन। शानलैक्स इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉमर्स, 5(4), 187-197।
10. कुमार एवं मोदी। (2017). सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में सरकार समर्थित बीमा योजनाएँ (पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई) का विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, 6(01), 351-362।
11. खंडेवाल, वी. (2017). प्रधानमंत्री जनधन योजना के प्रति जागरूकता और लाभों पर अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ फाइनेंस, 11(1)।